



संपादक सीमा गुप्ता

स्थानिय भाषाओं का जोर

बहुभाषिक देश होने की वजह से हमारे यहां प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का संवैधानिक प्रावधान है। यह अच्छा भी है, क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा में ही सही ढंग से रचनात्मक सोच विकसित कर पाता है। मगर शिक्षा संबंधी यही भाषायी सुविधा बच्चे के लिए असुविधा बन जाती है, जब वह उच्च शिक्षा के लिए जाता है। खासकर तकनीकी विषयों की पढ़ाई मातृभाषा में कराने की व्यवस्था विकसित ही नहीं की गई। तर्क यह दिया गया कि चूंकि तकनीकी शब्दावली के भारतीय भाषाओं में पर्याय बनाना जटिल काम है, इसलिए उनकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखना ही उचित होगा। हालांकि अब कुछ राज्य सरकारें ने हिंदी और दूसरी भाषाओं में इंजीनियरिंग, चिकित्सा आदि तकनीकी विषयों की पढ़ाई का प्रयास शुरू किया है, मगर पढ़ाने वालों के सामने भाषा संबंधी अड्डें बनी हुई हैं। इसलिए उच्च शिक्षा में बच्चों का अंग्रेजी से पिंड नहीं छूट पा रहा। वे जैसे-तैसे जोड़तोड़ कर अंग्रेजी में लिखी किताबों से सिद्धांतों और अवधारणाओं को तो आत्मसात कर लेते हैं, मगर जब परीक्षा देने की बारी आती है, तो उनके हथ-पांव ठंडे पड़ जाते हैं। अनेक मेधावी बच्चे भी परीक्षा में इसीलिए पिछड़ जाते हैं कि उत्तर अंग्रेजी में नहीं लिख पाते। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस अड्डचन को दूर करने का कदम उठाया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिख कर आग्रह किया है कि वे विद्यार्थियों को स्थानीय भाषाओं में भी परीक्षा देने का अवसर उपलब्ध कराएं। बेशक पाठ्यक्रम अंग्रेजी में हो, पर उन्हें सवालों का जवाब स्थानीय भाषा में लिखने का अवसर मिलना चाहिए। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से यह भी अनुरोध किया है कि तकनीकी विषयों की पुस्तकें स्थानीय भाषाओं में भी लैयर कराने का प्रयास होना चाहिए। यह एक तरह से उत्तरी कदम की अगली कड़ी है, जिसके तहत कुछ राज्य सरकारें तकनीकी विषयों की पाठ्यपुस्तकें भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने के प्रयास में जुटी हैं। यह विद्यार्थियों में आत्मविश्वास पैदा करने और प्रतिभा विकास की दृष्टि से तो अच्छी पहल है, मगर व्यावहारिक स्तर पर इसकी सफलता को लेकर सवाल बने ही रहेंगे। उच्च शिक्षा में केवल डिप्पी हासिल करना मकसद नहीं होता। उसमें शोध और अनुसंधान की स्वाभाविक अपेक्षा जुड़ी होती है। इसलिए विश्वस्तरीय शोध और अनुसंधान की दृष्टि से स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करना अड्डचन बन सकता है। फिर, व्यावहारिकता के स्तर पर इसकी उपयोगिता को लेकर बड़ा प्रश्नचिह्न लग जाता है। चिकित्सा विज्ञान में अद्यान शोधों की जानकारी के बिना काम नहीं चल सकता, इसे स्थानीय भाषा में ग्रಹण करना थोड़ा जटिल है। तर्क यह भी दिया जाता है कि जब सामाजिक विज्ञान और कला विषयों में विद्यार्थी अपनी मर्जी से भाषा माध्यम का चुनाव कर अपनी प्रतिभा को लोहा मनवा सकता है, तो तकनीकी विषयों में ऐसा बच्चे संभव नहीं है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी उदाहरण हैं, जिन्होंने आड्डाहटी में अपना शोध हिंदी में लिख कर जमा कर चुके हैं और उनकी प्रतिभा किसी से कम नहीं है। फिर कहा यह भी जाता है कि तकनीकी विषयों को व्यावहारिक उपयोग आविष्कार कर स्थानीय लोगों के बीच ही किया जाता है, इसलिए उन्होंने की भाषा में उसे अधिव्यक्त करना पड़ता है।

जनकल्पण संपादकीय

ठाणे | वर्ष - २२ | अंक - १४ | २४ से ३० अप्रैल २०२३ | पृष्ठ - ४ | कीमत : २ रु. | Postal Reg. No. PLG/08/2022-2024

जेकेएस संचालित

मीरा-भाईदर : दहिसर से भाईदर (पश्चिम) तक बन रही मेट्रो लाइन का उत्तर तक विस्तार होगा। इस संबंध ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में दुर्घटक में निर्णय लिया जा चुका है। एमएमआर वें प्रत्येक परिसर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत व नया जा एगा और इस रोजन में ३३५ किलोमीटर लंबे मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। ये बातें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहीं। वह महाराष्ट्र भवन और एक अस्पताल के भूमिपूजन के मौके पर मीरा-भाईदर आए थे। उन्होंने कहा कि मीरा-भाईदर का लोकेशन एक स्ट्रे ट्रिंक लोकेशन है। भविष्य में मीरा-भाईदर एमएमआर के विकास का बेंद्र बनेगा।



मीरा-भाईदर को एक स्ट्रे ट्रिंक लोकेशन हुआ। वहुमंजिला महावीर भवन में साथू-संतों में लिए निवास, भोजनालय के अलावा सार्वजनिक सभागृह, मीटिंग रूम, जिम, डोमेट्री जैसी भी व्यवस्था हो गी। तीन अलग-अलग कार्यक्रम में विधायक गीता जैन, पूर्व विधायक नंदें मेहता, पूर्व सासद विनय सहस्रबूद्धे, विधायक

राजहंस सिंह, बीजेपी नेता अमरजीत मिश्रा, बीजेपी जितायक दिलीप दोले आदि भौजूद थे। फडणवीस की उपस्थिति में बीते दिनों जारी एक सरकारी आदेश का उल्लंघन कक्ष का गया। विधि विधि खारघर ने उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों मीरा भाईदर कार्यक्रम के दौरान गर्मी और

दिहाइड्रेशन से हुई मौतों के कारण राज्य सरकार ने दोपहर १२ बजे से ४ बजे तक खुले में कार्यक्रम पर रोक लगा दी थी। उप मुख्यमंत्री ने नियम तोड़ते हुए तकरीबन १ बजे सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व ग्रामीण विकास के दौरान गर्मी और

ग्रंथालय व वाचनालय का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने २ बीं सदी का उत्तरार्द्ध ज्ञान की सदी होगा। ज्ञान परिमार्जित करने अध्यक्ष अमरजीत मिश्रा का अधिनंदन किया। सीए फाइनल ईयर की तैयारी कर रहे नारायण कुमारवत (२९) ने कहा कि ग्रंथालय का बहुत लाभ हुआ है।

ग्रंथालय के निर्माण के लिए उन्होंने पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और संचालन करने वाली संस्था अधियान के अध्यक्ष अमरजीत मिश्रा का अधिनंदन किया। सीए फाइनल ईयर की तैयारी कर रहे नारायण कुमारवत (२९) ने कहा कि ग्रंथालय का बहुत लाभ हुआ है।

पारंधी आदिवासी समाज काफी समय से उपेक्षा का शिकार



मुंबई। आदिवासी पारंधी समाज वर्ष से १९९५ से रह रहा है। लेकिन यह समाज बिजली, पानी, साफ सफाई जैसी बुनियादी चीजों से वंचित है। वहां की साफ सफाई और इसके साथ ही साथ अंगनवाड़ी शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसके अलावा घनसोली के सात सौ झोपड़ियों को मूलभूत सुविधा मुहैया कराइ जाए। ऐसी जानकारी आदिवासी समाज महाराष्ट्र के नेता संतोष पवार ने दिया है। इस मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले से तो अच्छी पहल है, मगर व्यावहारिक स्तर पर इसकी सफलता को लेकर सवाल बने ही रहेंगे। उच्च शिक्षा में केवल डिप्पी हासिल करना मकसद नहीं होता। उसमें शोध और अनुसंधान की स्वाभाविक अपेक्षा जुड़ी होती है। इसलिए विश्वस्तरीय शोध और अनुसंधान की दृष्टि से स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करना अड्डचन बन सकता है। फिर, व्यावहारिकता के स्तर पर इसकी उपयोगिता को लेकर बड़ा प्रश्नचिह्न लग जाता है। चिकित्सा विज्ञान में अद्यान शोधों की जानकारी के बिना काम नहीं चल सकता, इसे स्थानीय भाषा में ग्रहण करना थोड़ा जटिल है। तर्क यह भी दिया जाता है कि जब सामाजिक विज्ञान और कला विषयों में विद्यार्थी अपनी मर्जी से भाषा माध्यम का चुनाव कर अपनी प्रतिभा को लोहा मनवा सकता है, तो तकनीकी विषयों में ऐसा बच्चे संभव नहीं है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी उदाहरण हैं, जिन्होंने आड्डाहटी में अपना शोध हिंदी में लिख कर जमा कर चुके हैं और उनकी प्रतिभा किसी से कम नहीं है। फिर कहा यह भी जाता है कि तकनीकी विषयों को व्यावहारिक उपयोग आविष्कार कर स्थानीय लोगों के बीच ही किया जाता है, इसलिए उन्होंने की भाषा में उसे अधिव्यक्त करना पड़ता है।

सकारात्मक भूमिका लेकर वह जल्द ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे और इस मूदे को सुलझाएंगे। ऐसा आश्वासन भी दिया जाए। इसके अलावा नवी मुंबई के घनसोली के उठाया जाना चाहिए। उन्हें न्याय मिलना चाहिए। इस समय रावर ने रहने वाले काम को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की जानकारी पवार ने दी है।

संतोष पवार ने केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले से अपने उपर्युक्त अवधिकारी और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उपेक्षा का शिकार है। उन्होंने न्याय राज्य को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की जानकारी पवार ने दी है।

मनपा के संपत्ति कर विभाग को द्वितीय पुरस्कार से किया सम्मानित



द१७ नागरिकों ने ६६ करोड़ २७ लाख ०३ हजार ४१९ करी राशि का भुगतान किया है। जानकारी ९२ हजार ८९८ नागरिकों ने ३७ करोड़ ८८ लाख ३७ हजार ४६५ की राशि का भुगतान किया है। निर्देशनुसार कर वसूली के लिए नियंत्रण अधिकारी एवं संसाधन नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर अपर आयुक्त संभाजी पानपट्टु और उपायुक्त रवि पवार भी उपस्थित थे। मीरा भायंदर महानगरपालिका को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। महानगरप

